

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1573

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

"नल से जल" योजना के तहत झुग्गी बस्तियों में पेयजल

1573. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में झुग्गी बस्तियों के बारे में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास "नल से जल" योजना के तहत झुग्गी बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है;
- (घ) क्या बहुत-सी झुग्गी-झोपड़ियां ऐसी हैं, जो जल की दैनिक जरूरतों के लिए पानी की टंकी पर निर्भर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत की जनगणना देश में झुग्गियों सहित जनसंख्या के दशकीय आधार पर की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार देश भर में 1.39 करोड़ परिवारों वाले कुल 6.54 करोड़ लोग झुग्गियों में रह रहे थे। देश में झुग्गियों संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा एकत्र किए जाते हैं। एनएसएसओ द्वारा वर्ष 2012 में 69वें दौर के सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए झुग्गियों के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, देश में झुग्गियों की अनुमानित संख्या 33,510 है जिनमें 13,761 अधिसूचित झुग्गियां और 19,749 गैर-अधिसूचित झुग्गियां शामिल हैं। एनएसएसओ सर्वेक्षण 2012 के अनुसार झुग्गियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, जनगणना 2011 के अनुसार झुग्गी परिवार और झुग्गी जनसंख्या अनुबंध में दी गई है। जनगणना 2011 के अनुसार झुग्गियों में रहने वाली जनसंख्या और परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और शहर-वार ब्यौरा यूआरएल <https://pmay->

पर दिया गया है।

(ख) से (ड) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सूचित किया है कि 'भूमि' और 'कॉलोनाइजेशन' राज्य के विषय हैं। आवास और झुग्गी पुनर्वास से संबंधित योजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अलावा, जैसा कि सूचित किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे परियोजनाओं के लिए 35,990 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ 25 जून, 2015 को 500 चयनित शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। अमृत 2.0 को 01 अक्टूबर, 2021 को परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ शुरू किया गया था।

अमृत और अमृत 2.0 योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के भीतर झुग्गी बस्तियों सहित परियोजनाओं को डिजाइन करने, अनुमोदित करने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य की उच्च अधिकार-प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार अमृत के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) और अमृत 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को मंजूरी दी।

अमृत के तहत, अब तक 43,430.25 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,405 जलापूर्ति परियोजनाओं का कार्य जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है, जिनमें से 41,546.48 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। अमृत 2.0 के तहत, अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 1,14,275.19 करोड़ रुपये की 3,587 जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।

इसके अलावा, अगस्त 2019 से, गांवों में रहने वाले लोगों की उनके घरों में पाइपगत जल आपूर्ति की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन को लागू कर रही है, ताकि देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

अगस्त 2019 में, जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 10.02.2025 तक दी गई सूचना के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत लगभग 12.22 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 10.02.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.79%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएसएसओ सर्वेक्षण 2012 के अनुसार झुग्गियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और जनगणना - 2011 के अनुसार झुग्गी परिवार और झुग्गी जनसंख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरों की संख्या		झुग्गी परिवार	झुग्गी जनसंख्या	एनएसएसओ के अनुसार झुग्गी संख्या
	वैधानिक शहर	झुग्गी संसूचित शहर			
आंध्र प्रदेश*	125	125	24,31,474	1,01,86,934	4,539
अरुणाचल प्रदेश	26	5	3,479	15,562	-
असम	88	31	42,533	1,97,266	71
बिहार	139	88	2,16,496	12,37,682	655
छत्तीसगढ़	168	94	4,13,831	18,98,931	1,079
गोवा	14	3	5,497	26,247	-
गुजरात	195	103	3,45,998	16,80,095	2,923
हरियाणा	80	75	3,32,697	16,62,305	71
हिमाचल प्रदेश	56	22	14,385	61,312	47
जम्मू एवं कश्मीर	86	40	1,03,633	6,62,062	42
झारखंड	40	31	72,544	3,72,999	-
कर्नाटक	220	206	7,07,662	32,91,434	1,424
केरल	59	19	45,417	2,02,048	35
मध्य प्रदेश	364	303	11,17,764	56,88,993	1,635
महाराष्ट्र	256	189	24,99,948	1,18,48,423	7,723
मणिपुर	28	-	-	-	-
मेघालय	10	6	10,518	57,418	-
मिजोरम	23	1	15,987	78,561	-
नागालैंड	19	11	17,152	82,324	-
ओडिशा	107	76	3,50,032	15,60,303	756
पंजाब	143	73	2,93,928	14,60,518	597
राजस्थान	185	107	3,94,391	20,68,000	1,600
सिक्किम	8	7	7,203	31,378	-
तमिलनाडु	721	507	14,63,689	57,98,459	2,364
त्रिपुरा	16	15	34,143	1,39,780	-
उत्तर प्रदेश	648	293	10,66,363	62,39,965	1,814
उत्तराखंड	74	31	93,911	4,87,741	-
पश्चिम बंगाल	129	122	13,91,756	64,18,594	3,957
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1	3,324	14,172	-
चंडीगढ़	1	1	21,704	95,135	-
दादरा एवं नगर हवेली	1	-	-	-	-
दमण एवं दीव	2	-	-	-	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	22	3,67,893	17,85,390	458
लक्षद्वीप	0	-	-	-	-
पुदुचेरी	6	6	34,839	1,44,573	17
अखिल भारतीय	4,041	2,613	1,39,20,191	6,54,94,604	33,510#

नोट: मणिपुर, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण और दीव ने एनएसएसओ सर्वेक्षण 2012 और जनगणना 2011 के दौरान किसी भी झुग्गी और झुग्गी परिवार और झुग्गी जनसंख्या की सूचना नहीं दी।

* आंध्र प्रदेश के आंकड़ों में तेलंगाना भी शामिल है।

छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में झुग्गी संख्या उपलब्ध नहीं है, तथापि, वर्ष 2012 के दौरान एनएसएसओ के अनुमानों के अनुसार देश में कुल झुग्गी संख्या 33,510 थी।